तेजिंदर सिंह उर्फ काका

बनाम

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1279/2008 आदि)

11 अप्रैल, 2013

[चंद्रमौली केआर. प्रसाद और वी. गोपाला गौड़ा, जेजे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302, 376 (2) (छ) 201 और 506-सामूहिक बलात्कार और हत्या निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-अभिनिर्धारित किया: गवाहों की गवाही में बड़ी विसंगति है और दी गई जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करना मुखबिर द्वारा-इसके अलावा, जिस सरपंच को अभियुक्तों ने इकबालिया बयान दिया था, उसने सूचित किया अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त हैं - दोषी ठहराने और सजा देने के लिए सबसे अप्राकृतिक और अविश्वसनीय उन्हें-न तो निचली अदालत और न ही उच्च न्यायालय ने उनकी जांच की है। आरोपों पर निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए उसी की फिर से सराहना करके उचित रूप से गवाही-इस पर कोई भौतिक सबूत नहीं है। अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और सजा देने के लिए रिकॉर्ड-उनके

दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया जाता है-परिस्थितिजन्य सबूत।

अतिरिक्त - न्यायिक स्वीकारोक्ति - अभिनिर्धारित : एक कमजोर रूप है। साक्ष्य और ऐसे साक्ष्य के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं और अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त पर दंड लगाया जा सकता है।

भारत का संविधान, 1950:

कला. 142 - गैर-अपीलार्थी को बरी किए जाने का लाभ दिया गया। अभियुक्त भी-दंड संहिता, 1860-धारा 302, 376 (2) (छ), 201, 404 और 506 आई.पी.सी.।

धारा 302, 376(2)(जी), 148, 201 और 404 सहपठित धारा के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 25.5.2000 को पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 34 आईपीसी, आरोप है कि 24.5.2000 को लगभग 9 बजे। मृतक चारा लाने के लिए खेतों में गया था और वापस नहीं लौटा। लगभग सुबह 8 बजे 25.5.2000 को, मृतक का शव आरोपी 'एसएल' के गन्ने के खेत में एक ताजा खोदे गए गड्ढे में दबा हुआ पाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी 'जीएस' को धारा 302, 376(2)(जी) और 506 आईपीसी और आरोपी 'आरवी' के तहत दोषी ठहराया। 'एचएस', 'बीएस' और एसएल धारा 302, 376(2)(जी) और 404 आईपीसी के तहत। इन सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

आरोपी 'टीएस' को आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया और 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। अभियुक्त 'जीएस' को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्तों ने अपील दायर की।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 जहाँ तक अपीलार्थी 'टी.एस.' का संबंध है, आरोप आईपीसी की धारा 201 के तहत है। जैसा कि पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 के साक्ष्य से देखा जा सकता है, इसमें बड़ी विसंगति है उनके साक्ष्य के बयानों के बीच पीडब्लू-8 ने कहा है - उस अपीलार्थी 'टी. एस.' ने गन्ने के खेत में कुदाल के साथ एक गड्ढा खोदना शुरू किया, जबकि पीडब्लू-9 ने कहा है कि उक्त उस समय याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं थे। प्रमुख को देखते हुए गवाहों के बयानों के बीच विसंगति और विरोधाभास, यह न केवल एक गंभीर संदेह पैदा करता है। उक्त अपीलार्थी के अपराध का हिस्सा होने के बारे में लेकिन उस स्थान पर उसकी उपस्थिति को भी संदिग्ध बनाता है। आरोप पर अपीलार्थी 'टी.एस.' के खिलाफ निष्कर्ष और दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित करना जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, उचित सराहना के बिना है। अपीलार्थी के स्थान पर अपीलार्थी 'टी.एस.' की उपस्थिति के संबंध में पीडब्लू 8 और 9 के बयानों में प्रमुख विसंगति घटना। नीचे की अदालतें भी ऐसा करने में विफल रही हैं। पीडब्लू-10 के

साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसने घटना स्थल के पास अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति के बारे में गवाही दी थी, लेकिन उसने अपीलार्थी का नाम नहीं लिया है 'टीएस। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी 'टी.एस.' के खिलाफ अपने मामले को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी ठोस और सकारात्मक सबूत नहीं रखा गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को इससे आगे भी उचित संदेह साबित किया है। सन्देह का लाभ होना चाहिए विवादित निर्णय में 'टी. एस.' तक बढ़ा दिया गया। उच्च न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य की पुनः सराहना करते हुए। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। [पैरा 18, 20 और 21] [817-डी-ई, एफ-एच; 818-ए-ई, एफ-एच]

सुखराम बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 (9) एससीआर 44 = 2007 (7) एस.सी.सी. 502-पर निर्भर।

1.2 इस प्रकार, यह न्यायालय मानता है कि प्रमुख है गवाहों पीडब्लू-8 और पीडब्लू 9 की गवाही में विसंगति और सूचना देने वाले द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाती है। निचली अदालत का निष्कर्ष इस संबंध में कानूनी रूप से गलत है क्योंकि पीडब्लू 8 और 9 के साक्ष्य ने गंभीर संदेह पैदा किया है और संदेह, इसलिए, इसे अन्य अपीलार्थियों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। [पैरा 22] [820-ए-सी]

1.3 इसके अलावा, पीडब्लू-7, जिसे सह-अभियुक्त अर्थात्, 'जी.एस.', 'एच.एस.' और 'एस.एल.' ने एक खुलासा बयान दिया 12.06.2000 पर उसे पूरी घटना का वर्णन करते हुए, न तो कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दर्ज की गई है और न ही उक्त कथन का खुलासा किया लेकिन पुलिस को सूचित करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का खुलासा करने में 16 दिन लगे। अतिरिक्त न्यायिक इकबालिया बयान के बारे में पुलिस को सूचित करने में देरी कथित तौर पर कुछ अभियुक्तों ने उससे बलात्कार किया है। पीडब्लू-7 द्वारा समझाया नहीं गया है और इसका कारण बताया गया है। पुलिस को इसका खुलासा न करने के लिए उनके द्वारा दिया गया। इसलिए, पीडब्लू 7 के साक्ष्य पर निर्भरता रखी गई। निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराने और उसे आई.पी.सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए सजा सुनाने के लिए कानून में गलत है। [पैरा 23 और 25] [820-डी-एफ; 823-जी]

द्वारकादास गेहनमल बनाम गुजरात राज्य 1999 (1) एस.सी.सी. 57-निर्भर।

1.4 इसके अलावा, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति कमजोर है। दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाई जा सकती है। अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त। [पैरा 24] [821-बी]

पंचो बनाम हरियाणा राज्य 2011 (12) एस. सी. आर. 1173 = 2011 (10) एस.सी.सी. 165; और सहदेवन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य 2012 (4) एससीआर 366 = 2012 (6) एससीसी 403-भरोसा किया।

1.5 जहां तक संबंधित अपीलों में अन्य अपीलकर्ताओं का संबंध है, ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-7, पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 के सबूतों पर भरोसा करने के बाद उनके खिलाफ आरोपों पर निष्कर्ष दर्ज किया है, जो कानून में पूरी तरह से अक्षम्य है न तो ट्रायल कोर्ट और न ही हाई कोर्ट ने आरोपों पर निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए उनकी गवाही की दोबारा सराहना करके ठीक से जांच की है। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपियों के खिलाफ कथित अपराधों का वर्णन उन्हें दोषी ठहराने और सजा देने के लिए सबसे अप्राकृतिक और अविश्वसनीय है। निचली अदालतों को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की उचित सराहना करनी चाहिए थी और पीडब्लू-8 के सबूतों के बयान पर विश्वास नहीं करना चाहिए था क्योंकि न तो उन्होंने अपीलकर्ताओं और अन्य अभियुक्तों द्वारा किए गए कथित अपराधों का खुलासा किया था और न ही उन्होंने गवाही दी थी। ट्रायल कोर्ट के समक्ष या ग्रामीणों में से किसी के समक्ष। उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया, उसमें कहा गया कि उन्हें डर के कारण रोका गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया पीडब्लू-8 के साक्ष्य के

बयान पर विश्वास नहीं किया है कारण कि न तो उसने अपीलार्थियों द्वारा किए गए कथित अपराधों का खुलासा किया है और अन्य अभियुक्तों ने न तो मुकदमे से पहले गवाही दी। अदालत या गाँव के किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्टीकरण दिया गया है। उनके द्वारा कि उन्हें डर से पकड़ लिया गया था और इसलिए, उन्होंने पीडब्लू-8 पर इस न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया जा सकता है। [पैरा 27] [824-डी-एच; 825-ए]

1.6 पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 की गवाही स्पष्ट रूप से होगी। यह दिखाने के लिए जाएँ कि इसके बारे में एक विसंगति है अभियुक्त द्वारा किए गए अपराधों का वर्णन। इसलिए, निचली अदालतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 के साक्ष्य पर भरोसा किया है और निष्कर्ष दर्ज किया है कि उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त साबित हुए। नीचे की दोनों अदालतों ने निर्भरता रखने में गंभीर त्रुटि की है। पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 की अविश्वसनीय गवाही पर और उनके खिलाफ दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित करना। इसके अलावा, अन्य गवाह, अर्थात् पीडब्लू-10 के साक्ष्य से, अपराध का आरोप लगाया गया है। उक्त अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 27 और 28] [825-ए-सी; डी-ई]

1.7 निचली अदालतों ने अपीलार्थियों को उनके खिलाफ बनाए गए आरोपों के आधार पर दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है। परिस्थितिजन्य

साक्ष्य पर, भले ही की श्रृंखला अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं को घर लाने के लिए साबित नहीं किया जाता है लगाए गए आरोपों पर अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों का अपराध उनके खिलाफ। आरोपों पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष कानूनी के खिलाफ है। इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित सिद्धांत। अभियुक्त के लिए अपीलार्थियों/ अभियुक्तों की दोषसिद्धि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर अपराध गवाह कानून में त्रुटि से पीड़ित हैं। [पैरा 28 और 31] [825 जी-एच; 826-एच; 827-ए-बी]

1.8 अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और सजा देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं है। गुजरने के बाद संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष का मामला अभियोग पर अपीलार्थी/अभियुक्त संदेह पैदा करते हैं और अभिलेख पर कानूनी साक्ष्य के अभाव में संदेह और इसलिए, उसी के लाभ के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्हें बरी करने के लिए अभियुक्त। उनका विश्वास और वाक्य अलग रखे जाते हैं। [पैरा 30 और 32] [826-जी; 827-सी]

2. अभियुक्त, अर्थात 'जी.एस.' 'जिसे भी दोषी ठहराया गया है। आई.पी.सी. की अन्तर्गत धारा 302, 376 (2) (जी) और 506 के तहत और सजा सुनाई गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त कारावास और द्वारा पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय को इस न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग

करते हुए अनुच्छेद 142 के तहत समान लाभ दिया जाता है। संविधान, और उसे रिहा करने का भी निर्देश दिया जाता है। [पैरा 33] [827-डी-ई]

टी. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य 2006 (1) एससीआर 180 = (2006) 1 एस.सी.सी. 401-उद्धृत।

मामला कानून संदर्भः

2006 (1) एससीआर 180	उद्धृत किया गया	पैरा 12
1999 (1) एससीसी 57	भरोसा करें	पैरा 12
2011 (12) एससीआर 1173	भरोसा करें	पैरा 12
2012 (4) एससीआर 366	भरोसा करें	पैरा 12
2007 (9) एससीआर 44	भरोसा करें	पैरा 12

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील 1279/2008।

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2004 की सीआरएल.ए. संख्या 716-डीबी में पारित 05.06.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

साथ

2008 की सीआरएल.ए संख्या 1280, 1281 और 1282।

के.टी.एस. तुलसी, फखरुद्दीन (ए.सी.), कुबेर बोध, कार्तिकेय (के लिए अरुण कुमार बेरीवाल), शीबा फखरुद्दीन, सूर्य कमल मिश्रा के लिए अपीलार्थी।

संचर आनंद, एएजी, अरुण के. सिन्हा, कुलदिप सिंह के लिए उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय वी. गोपाला गौड़ा, जे. द्वारा दिया गया था।

1. ये आपराधिक अपीलें हैं - 05.06.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2004 की आपराधिक अपील संख्या 716-डी. बी. में पारित किया गया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्तों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। 376 (2) (छ), 148, 201, 404 भारतीय संविधान की धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है। कारावास की विभिन्न सजाओं के साथ दंड संहिता जो चलाने के लिए निर्णय के बाद के भाग में संदर्भित किया जाए। समवर्ती रूप से और उन पर लगाया गया जुर्माना उसी आधार के तहत है। अपीलार्थियों द्वारा इन अपीलों में चुनौती देने के लिए विभिन्न आग्रह किए गए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 और 4 के तहत बनाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

2. अपीलार्थियों ने अपीलों को अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करते हुए और इनमें बनाए गए कानून के प्रश्नों के समर्थन में विभिन्न तथ्यों और आधारों का आग्रह करने वाले सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दें।

प्रतिद्वंद्वी तथ्यात्मक और कानूनी की उचित सराहना के लिए अभियोजन पक्ष के मामले के संबंध में प्रासंगिक तथ्य संक्षेप में हैं जैसा कि नीचे बताया गया हैः

3. 25.05.2000 पर, सीसो के रिश्तेदार नागो राम, पुत्र मुंशी राम के बयान के आधार पर पुलिस स्टेशन बंगा, नवांशहर में प्राथमिकी संख्या 73 दर्ज की गई थी। मृतक, आई.पी.सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, 376 (2) (जी), 148, 201, 404 के तहत अपराधों के लिए यह आरोप लगाते हुए कि 24.05.2000। सुबह लगभग 9 बजे मृतक चारा लाने के लिए खेत में गया और जब वह दोपहर तक घर नहीं लौटी, तो सूचना देने वाले उन्होंने उसकी तलाश शुरू की लेकिन वे कोई जानकारी इकट्ठा नहीं कर सके। यह आरोप लगाया गया था कि 25.05.2000 को सुबह 8 बजे, सूचना देने वाला अन्य लोगों के साथ गन्ने के खेत में खोजबीन करने गए। मृतक के लिए जहाँ उन्हें एक ताजा गड्ढा भरा हुआ मिला मिट्टी के साथ जिसके अंदर शव दफनाया गया था। एक पल्ली से ढकी मिट्टी। यह भी आरोप लगाया गया कि मृतक के शव से सोने की

कान की अंगूठियां, चांदी की चूड़ियां और पायलें मिली थीं। मृतक लापता पाए गए। यह सूचना देने वाले ने आरोप लगाया था कि जमीन के मालिक सनी लाल पासवान ने हत्या करने के बाद तीन चार लोगों के साथ मृतक शव को दफना दिया।

4. उक्त एफ.आई.आर. दर्ज करने के आधार पर मामले की जांच की गई और संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दी गई। दंड प्रक्रिया को समादेशित अदालत के समक्ष दायर किया गया था और उसके बाद उसने मामले को विद्वत अतिरिक्त को सौंप दिया है। सत्र न्यायाधीश, नवांशहर और मामला सुनवाई के लिए चला गया। अभियुक्त ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और आरोपों के लिए उन पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। ये आरोप धारा 304, 372, 376 (2) (जी), 148, 201, 404 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बनाए गए थे। आई.पी.सी. की धारा 34 के साथ और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की धारा 3 और 4 के तहत भी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रोकथाम) अत्याचार) अधिनियम, 1989। अभियोजन पक्ष गवाह पीडब्लू-1 से पीडब्लू 15 जाँच की गई और साक्ष्य का बयान विद्वान अतिरिक्त अधिकारी द्वारा गवाहों को दर्ज किया गया था। सत्र न्यायाधीश। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न सजाओं के साथ अभियुक्त जुर्माना जैसा कि बाद के भाग में

निर्णय विस्तार से निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय पारित करके इसकी पुष्टि की जाती है। उसी की शुद्धता है अपीलार्थियों द्वारा इन अपीलों में कुछ उठाकर चुनौती दी गई। कानूनी प्रश्न और उसी के समर्थन में आधार का आग्रह करना।

5. यह अपीलकर्ता श्री के.टी.एस. के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया है। तुलसी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले के महत्वपूर्ण पहलू, अर्थात् पीडब्लू-9 निरंजन राम, कथित अपराधों का तथाकथित एकमात्र चश्मदीद गवाह, जो स्पष्ट रूप से एच है, को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने साक्ष्य में कहा कि 24.05.2000 को लगभग 10.30 बजे। खुद को आराम देने के लिए, वह गाँव के पूर्वी हिस्से की ओर चला गया जहाँ मेला लगा हुआ था। अपने हाथ धोने के लिए वह ट्यूबवेल की ओर गया था, जहां उसने कुछ चीखें सुनीं और देखा कि भजन राम बी की पत्नी सीसो जमीन पर पड़ी थी और आरोपी गुरदीप सिंह ने उसकी बाहें पकड़ रखी थीं, आरोपी बलविंदर सिंह और राजिंदर कुमार ने सीसो के पैर ऊपर उठा रखे थे और आरोपी हरनेक सिंह उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. आरोपी सन्नी लाल और हरनेक ने सीसो की बांहें पकड़ रखी थीं। इसके बाद आरोपी गुरदीप सिंह ने सीसो की गर्दन पर कस्सी का वार कर दिया। यह देखते ही उसकी चीख निकल गई। पीडब्लू-9 को देखते ही आरोपी गुरदीप सिंह ने हाथ में कस्सी लेकर उसका पीछा किया और उसे धमकी दी

कि अगर उसने गांव में घटना का खुलासा किया तो उसके और उसके परिवार के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। डी गुरदीप सिंह द्वारा दी गई धमकी के डर से, पीडब्लू-9 ने किसी भी ग्रामीण या मृतक के परिवार के सदस्यों को घटना का खुलासा नहीं किया।

6. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. टी. एस. तुलसी ने इसका आग्रह किया है। 2008 के सीआरएल.ए संख्या 1279 में अपीलार्थी और श्री फखरुद्दीन के लिए, विद्वान वरिष्ठ वकील जो न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। संबंधित अपीलों में कि अपराधों का वर्णन करने वाले गवाहों के साक्ष्य के बयान को किया गया है। अपीलार्थियों द्वारा विश्वास करना सबसे अप्राकृतिक और असंभव है। इन अपीलार्थियों के संबंध में मामले के इस पहलू की उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से सराहना नहीं की गई है। विद्वानों द्वारा उन पर लगाए गए दोषसिद्धि और दंड अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी प्रस्तुत करता है कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-9 की गवाही पर भरोसा करते हुए विवादित फैसले में साक्ष्य के उनके संक्षिप्त बयान को निकालकर दोषसिद्धि के साथ सहमति व्यक्त की है और अतिरिक्त द्वारा अपीलार्थी पर उच्च न्यायालय अधिरोपित दंडादेश सत्र न्यायाधीश और उसी की ओर से गलत है। इसलिए, एक तरफ वह प्रस्तुत करता है कि वही निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

7. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने गलती से पीडब्लू-8 चेत राम, के बहनोई की गवाही पर भरोसा किया है। मृतक, जो घटना का चश्मदीद गवाह भी नहीं है। पीडब्लू 8 अपने साक्ष्य में कहा कि उसने आरोपी गुरदीप सिंह हरनेक सिंह, बलविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह और सनी लाल पासवान को देखा था, एक पल्ली में कुछ भारी सामग्री ले जा रहे थे और उन्होंने उसे गन्ने के खेत में रख दिया था। आरोपित तेजिंदर सिंह ने कुदाल की मदद से खेत में गड्ढा खोदा और पृथ्वी के नीचे सामग्री को दफना दिया। उसके पूछने पर आरोपी गुरदीप सिंह ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या किया था। कि उसके साथ भी उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा और कहा जाएगा शब्द "कुटिया चमारा तेरा भी इहो हल करंगे"। इसके बाद आरोपी गुरदीप सिंह हाथ में कस्सी लिए भाग गया उसे। डर के मारे वह गांव की ओर भाग गया।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ तक कि उपरोक्त गवाह के बयान को सच मानते हुए, मृतक का बहनोई होने के नाते परिवार को भी घटना की जानकारी नहीं देना बहुत ही असामान्य और अप्राकृतिक है। सदस्यों या पुलिस को। इस मामले का यह पहलू नहीं है। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है, यह अनदेखी की है। पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 के बीच गवाहों के बयानों में प्रमुख विसंगति,

जिनके साक्ष्य पर पूरा अभियोजन पक्ष मामला आधारित है। पीडब्लू-8 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अपीलार्थी तेजिंदर सिंह ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया जबकि पीडब्लू-9 ने तेजिंदर सिंह पर आरोप लगाने वाले अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से गवाही दी। उस समय वहाँ नहीं थे।

9. उपरोक्त गवाह का बयान न केवल अपीलार्थी तेजिंदर सिंह के बारे में एक गंभीर संदेह पैदा करता है। अपराध करने की साजिश का हिस्सा लेकिन उसकी उपस्थिति भी घटना स्थल पर। उपरोक्त गवाह के साक्ष्य में इस प्रमुख विसंगति पर विचार न करना दोनों द्वारा विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि कानून में गलत आरोपों पर निष्कर्ष और इसलिए समान अलग रखे जाने की संभावना है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय पर विफल रहा है। पीडब्लू-10 कृष्ण के साक्ष्य की फिर से सराहना करें, जिनके पास है। बयान में आरोपी व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपीलकर्ता तेजिंदर सिंह की अपराधों में संलिप्तता का नाम नहीं लिया है, जैसा कि पीडब्लू-8 चेत राम के बयान में आरोप लगाया गया है, जो एक बड़ा संदेह पैदा करता है।

10. अपीलकर्ता तेजिंदर सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है। 2008 की सीआरएल.ए. संख्या 1279 में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने कानून के सुस्थापित सिद्धांत का पालन नहीं किया कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में, अपीलीय अदालत का

कर्तव्य है कि वह रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना करे और आरोपी को उचित संदेह का लाभ दिया जाए। इसके द्वारा नहीं किया गया है. इस प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, टी. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य (2006) 1 एससीसी 401) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। इसके अलावा, अपनी दलील को विस्तार से बताते हुए, उन्होंने आग्रह किया है कि यदि एक ही साक्ष्य से दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया है। घटना के स्थान पर अपीलकर्ता तेजिंदर सिंह की उपस्थिति के बारे में गंभीर संदेह है, जो अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ में जाता है जहां तक कथित अपराध करने में अपीलकर्ता की भूमिका का सवाल है।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने एक अन्य गवाह भूपिंदर सिंह पीडब्लू-7, (तत्कालीन सरपंच) के साक्ष्य को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया है और कथित तौर पर उसके साक्ष्य के बयान में निहित असंभवताओं को नजरअंदाज करते हुए उसे एक विश्वसनीय गवाह माना है। कहा जाता है कि सीआरएल.ए में अपीलकर्ता के अलावा अन्य तीन आरोपी व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की गई थी। 2008 की संख्या 1279 और ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने उसी पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष दर्ज किया कि उक्त अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हुआ है और कथित अपराध के लिए उसे दोषी

ठहराया गया और सजा दी गई। निचली अदालतों का यह निष्कर्ष कानून की नजर में गलत है और एक तरफ इसे रद्द किया जा सकता है। पीडब्लू-7 के बयान के अनुसार, जिसने 28.5.2000 आरोपी गुरदीप सिंह, हरनेक सिंह और सनी लाल पासवान ने उन्हें एक खुलासा बयान दिया। पूरी घटना का वर्णन करें। कथित खुलासा बयानों के 16 दिनों के बाद उसने पुलिस को इसका खुलासा किया है। कहा जाता है कि उसने उक्त अभियुक्त द्वारा उसे बनाया था और उसने 12.06.2000 पर आरोपी को पुलिस हिरासत में सौंप दिया। उनके द्वारा दी गई 16 दिनों की देरी का कारण यह था कि वह किसी काम में व्यस्त था और इसलिए, एक घटना की सूचना देने में 16 दिनों की अत्यधिक देरी पुलिस उक्त गवाह की ओर से असंतोषजनक बनी हुई है। जिनके लिए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का आरोप लगाया गया था। सह-अभियुक्त द्वारा बनाया गया। यह पीडब्लू-7 के आचरण को संदिग्ध और उसकी गवाही की सामग्री को संदिग्ध प्रकृति का बनाता है। इसके अलावा, वह लेने के बजाय गाँव का सरपंच है। आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही बलात्कार, हत्या और सबूतों को नष्ट कर दिया है, 16 दिनों के अंतराल के बाद पुलिस को सूचित किया। ऐसा नहीं हो सकता है। इस न्यायालय ने विश्वास किया।

12. उनके द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि यह प्रासंगिक है कि यह उल्लेख करें कि जिस काम में वे व्यस्त थे, उसकी तात्कालिकता के

बारे में उन्होंने कहीं भी नहीं बताया था। विद्वान वरिष्ठ वकील नियुक्त द्वारकादास गेहनमल में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता बनाम गुजरात राज्य (1999) 1 एससीसी 57) उनके कानूनी निवेदन के समर्थन में कि यदि गवाह का आचरण के आचरण के साथ असंगत है। एक साधारण मनुष्य की गवाही में कोई विश्वास नहीं है। स्वीकृति के लिए। द्वारकादास गेहनमल के मामले का अनुच्छेद 14 (ऊपर) निम्नानुसार हैः

> "14.....देव राम पीडब्लू-4 ने पाँच का इंतजार नहीं किया होगा। द्वारा की गई कथित स्वीकारोक्ति का खुलासा करने के लिए दिन उसे अपील करने वाला लेकिन इसके विपरीत, वह या तो होगा के इकबालिया बयान के आधार पर शिकायत अपीलार्थी और/या के घर गया होगा। नूरभाई परिवार के सदस्यों को इसके बारे में सूचित करेंगे। अपीलार्थी का इकबालिया बयान.....''।

इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि उपर्युक्त संदर्भित मामले में की गई टिप्पणियाँ समर्थन करेंगी। इसमें अपीलार्थियों का मामला विद्वान वरिष्ठ वकील ने विभिन्न पर निर्भरता रखी है

इस न्यायालय के अन्य निर्णय जिनमें अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति है बनाया गया था। प्रासंगिक अनुच्छेदों में निकाला जाएगा। इस निर्णय का उचित तर्क भाग सराहना करने के लिए उसके द्वारा की गई कानूनी प्रस्तुति

और अलग रखने के लिए विवादित निर्णय देना और बरी करने का आदेश पारित करना।

13. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री तुलसी ने भरोसा किया है। उनके कानूनी प्रस्तुतियों के समर्थन में निम्नलिखित मामले यह तर्क देते हुए कि सभी चार मामलों में यही बात लागू होगी, अर्थात् पंचो बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 10 एससीसी 165), सहदेवन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2012) 6 एससीसी 403) और सुखराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 7 एससीसी 502)।

14. विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री फखरुद्दीन जो हैं, संबंधित अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले लोगों ने भी अपनी दलीलें दी हैं, जिसमें समान आधारों का आग्रह किया गया है। श्री तुलसी, 2008 के सीआरएल.ए संख्या 1279 में पी. डब्ल्यू.-7 के संबंध में साक्ष्य के संबंध में अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील कुछ अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से उसे दिए गए अतिरिक्त न्यायिक इकबालिया बयान के लिए। इसके अलावा, उन्होंने आमंत्रित किया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों पर हमारा ध्यान यह दर्शाता है कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा अभियुक्त के खिलाफ दर्ज किए गए निष्कर्ष न केवल गलत हैं, बल्कि कानून में भी त्रुटि से ग्रस्त हैं और इसलिए अपीलों को अनुमति देकर उन्हें दरकिनार किया जा सकता है।

15. दूसरी ओर, श्री संचार आनंद, विद्वान पंजाब राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस पर दर्ज किए गए निष्कर्षों और कारणों को सही ठहराने की मांग की है। अदालतों द्वारा इसमें अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोप। निचली अदालत मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत होने के नाते, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना की और अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का यह मानते हुए जवाब दिया कि वे किए गए अपराधों के दोषी हैं मृतक के खिलाफ और तदनुसार उन्हें सुनने के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। विभिन्न अपराधों के लिए अभियुक्त को कारावास नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया हैः

दोषी का नाम	इस अनुभाग के अंतर्गत	वाक्य
गुरदीप सिंह	302 आईपीसी	आजीवन कारावास और Rs.10,000/का जुर्माना एक वर्ष के लिए आगे।
	376(2)(जी)आईपीसी	आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये का जुर्माना। डिफॉल्ट में एक वर्ष के लिए अतिरिक्त आरआई।

	506 आईपीसी	5 साल के लिए आरआई और 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा या डिफ़ॉल्ट पर 6 महीने के लिए अतिरिक्त आरआई का भुगतान करना होगा।
राजिंदर कुमार	302 आईपीसी	आजीवन कारावास एवं 10,000/-रूपये का जुर्माना। डिफॉल्ट में एक वर्ष के लिए अतिरिक्त आरआई।
	376(2)(जी)आईपीसी	आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये का जुर्माना। डिफॉल्ट में एक वर्ष के लिए अतिरिक्त आरआई।
	404 आईपीसी	1 वर्ष के लिए आरआई और रु. 1000/- का जुर्माना देना होगा या डिफ़ॉल्ट पर 1 महीने के लिए अतिरिक्त आरआई का भुगतान करना होगा।

हरनेक सिंह उर्फ नाका	302 आईपीसी 376 (2)(जी) आईपीसी 404 आईपीसी	डिफ़ॉल्ट पर आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना और एक वर्ष के लिए आरआई। आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये का जुर्माना। डिफॉल्ट में एक वर्ष के लिए अतिरिक्त आरआई। 1 वर्ष के लिए आरआई और रु. 1000/- का जुर्माना देना होगा या डिफ़ॉल्ट पर 1 महीने के लिए अतिरिक्त आरआई का भुगतान करना होगा।
बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर	302 आईपीसी 376(2)(जी)आईपीसी	आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये का जुर्माना। डिफॉल्ट में एक वर्ष के लिए अतिरिक्त आरआई। आजीवन कारावास एवं

	404 आईपीसी	10,000/- रूपये का जुर्माना। डिफॉल्ट में एक वर्ष के लिए अतिरिक्त आरआई। आरआई को 1 साल की कैद और 1000/ रुपये का जुर्माना देना होगा. या डिफ़ॉल्ट रूप से 1 महीने के लिए अतिरिक्त आरआई।
सन्नी लाल पासवान	302 आईपीसी 376(2)(जी)आईपीसी 404 आईपीसी	आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये का जुर्माना। डिफॉल्ट में एक वर्ष के लिए अतिरिक्त आरआई। आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये का जुर्माना। डिफॉल्ट में एक वर्ष के लिए अतिरिक्त आरआई। 1 वर्ष के लिए आरआई और

		1000 रुपये का जुर्माना देना होगा या डिफ़ॉल्ट पर 1 महीने के लिए अतिरिक्त आरआई का भुगतान करना होगा।
तेजिंदर सिंह उर्फ काका	201 आईपीसी	7 साल के लिए आरआई और 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा या डिफ़ॉल्ट पर 6 महीने के लिए अतिरिक्त आरआई का भुगतान करना होगा।
हालाँकि, कारावास की सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।		

16. यह आगे विद्वान अतिरिक्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महाधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए मामले में निष्कर्षों और कारणों की शुद्धता उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में गवाहों की गवाही निकालने और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में आग्रह किए गए कानूनी आधारों की पृष्ठभूमि में अपने दिमाग को लागू करने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जांच की गई। उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड करके दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की वैध और ठोस कारण निर्धारित करके आरोपों पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं

है। अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप भारत के संविधान का अनुच्छेद 136।

17. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी के संदर्भ में पक्षकारों की ओर से आग्रह की गई दलीलें, इस न्यायालय को इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या विवादित निर्णय में अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर समवर्ती विवादित निष्कर्ष गलत हैं और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है और क्या दोषसिद्धि और सजा पर लगाया गया है। पीडब्लू-7, पीडब्लू-8 के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी और पीडब्लू-9 और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाह कानूनी और वैध हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता है..?

18. उपरोक्त बिंदुओं का उत्तर निम्नलिखित कारणों से अपीलार्थियों के पक्ष में दिया जाना आवश्यक हैः

7 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा रूपये 5000/- या डिफ़ॉल्ट रूप से, आगे कठोर कार्रवाई से गुजरने के लिए 6 महीने की कैद। इस मामले के इस पहलू पर हम तथ्यात्मक और कानूनी पृष्ठभूमि में विचार करते हैं।

19. आई.पी.सी. की धारा 201 के दायरे को समझने के लिए सुखराम (उपरोक्त) के मामले को संदर्भित करना उचित है। निर्णय के तर्क भाग में उनकी दलीलों की सराहना करने के लिए प्रासंगिक पैराग्राफ निकाले जाएंगे।

20. जैसा कि पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 के साक्ष्य से देखा जा सकता है, उनके बयानों के बीच बड़ी विसंगति है सबूत। पीडब्लू-8 चेतराम ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अपीलार्थी तेजिंदर सिंह ने गन्ने के खेत में कुदाल से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था, जबकि पीडब्लू-9 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उक्त अपीलार्थी उस समय उपस्थित नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए एक गवाह और दूसरे गवाह के बयानों के बीच बड़ी विसंगति और विरोधाभास, यह न केवल एक कब्र पैदा करता है। उक्त अपीलार्थी के अपराध का हिस्सा होने के बारे में संदेह लेकिन उस स्थान पर अपनी उपस्थिति को भी संदिग्ध बनाता है। विद्वान वरिष्ठ वकील जो विद्वान सत्रों में न्याय करते हैं। उक्त गवाहों की गवाही पर भरोसा रखना और उपरोक्त अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज करना आरोप और दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित करना जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, उचित नहीं है। घटना के स्थान पर उपरोक्त अपीलार्थी। अदालतें नीचे दिए गए साक्ष्य को भी ध्यान में रखने में विफल रहे हैं पीडब्लू-10 कृष्णा, जिसमें उसने इस मामले में गवाही दी थी कि वह लगभग 8 बजे सुबह निमो के साथ चली गई थी खेतों से चारा लेना। लगभग 9 बजे जब वे वापस आ रहे थे, उन्होंने पाया कि सनी लाल मैदान में पानी पिला रहा था। इस बीच, मृतक अपने हाथों में जूट का कपड़ा लेकर खेतों में घुस गया। आरोपी बिंदर और काका ट्यूबवेल की ओर जाते हुए देखा गया।

आरोपी गुरदीप सिंह और हरनेक सिंह को भी स्कूटर पर ट्यूबवेल की ओर जाते देखा गया था, लेकिन उन्होंने अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया है के संबंध में पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 के साक्ष्य के बयान इस अपीलार्थी की अपराध करने में भागीदारी, जैसा कि उसके खिलाफ आरोप लगाया गया है।

21. इसके अलावा, कुछ भी ठोस और सकारात्मक नहीं है द्वारा उपरोक्त अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलेख में रखा गया साक्ष्य प्रस्ताव हाथ में मामले पर लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को इससे आगे भी साबित कर दिया है उचित संदेह। अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अभिलेख पर साक्ष्य की पुनः सराहना करते हुए उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में तेज इंदर सिंह को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था क्योंकि वह इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि अनुपात ऊपर निर्दिष्ट सुखराम के मामले में पैरा 18 में निर्धारित कि आई.पी.सी. की धारा 201 के तहत अपराध का गठन करने के लिए निम्नलिखित सामग्री अर्थात (i) से (iv) तक स्थापित किया जाना हैः-

> "18.....धारा 201 के तहत अपराध को घर लाना आई.पी.सी., स्थापित किए जाने वाले तत्व हैंः (i) वचनबद्ध किसी अपराध का; (ii) अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति धारा 201 में विश्वास करने का ज्ञान या कारण होना चाहिए

कि कोई अपराध किया गया है; (iii) अभियुक्त व्यक्ति उक्त अपराध के कारण गायब होना चाहिए था साक्ष्य का; और (iv) अधिनियम के साथ किया जाना चाहिए था। अपराधी की कानूनी जाँच करने का इरादा माना जाता है कि यह गलत है। यह स्पष्ट है कि स्क्रीन करने का इरादा अपराध करने वाला अपराधी प्राथमिक होना चाहिए और अभियुक्त का एकमात्र उद्देश्य। इसे शायद ही कोई जोर देने की आवश्यकता है कि धारा 201 के तहत अपराध को घर लाने के लिए आई.पी.सी., केवल संदेह पर्याप्त नहीं है। वहाँ होना चाहिए यह साबित करने के लिए ठोस सबूत दर्ज करें कि आरोपी जानता था या उसके पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त जानकारी थी कि अपराध किया गया था और आरोपी ने सबूत गायब होने के कारण स्क्रीन करने के लिए अपराधी, ज्ञात या अज्ञात।

19. पलविंदर कौर बनाम। पंजाब राज्य के इस न्यायालय ने 201 आई.पी.सी., यह साबित करना आवश्यक है कि एक अपराध किया गया है कि अभियुक्त को पता था या उसके पास कारण था विश्वास है कि इस तरह का अपराध किया गया था; आवश्यक ज्ञान और जांच करने के इरादे से

कानूनी सजा से अपराधी, सबूत का कारण बना गायब होने या गलत जानकारी देने के लिए ऐसा अपराध यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण होने के कारण झूठ होने के समान। यह देखा गया कि अदालत को अपने निष्कर्ष को आधार बनाने के खतरे से खुद को बचाएँ हालाँकि, संदेह पर वे मजबूत हो सकते हैं। (यह भी देखें सुलेमान रहिमान मुलानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य, नाथू बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, वी. एल. ट्रेसा बनाम। केरल राज्य।)

22. ऊपर बताए गए कारणों के लिए हमें इस निर्णय में एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि इसमें बड़ी विसंगति है। पी.डब्ल्यू.-8 और पी.डब्ल्यू.-9 गवाहों की गवाही और पंजीकरण भी सूचना देने वाले द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई, जाँच की गई और आरोप पत्र दायर किया गया और अपीलार्थी पर आरोपों के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था और सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया और अपराध के लिए सजा सुनाई। यह निष्कर्ष कानून में गलत है। इस कारण से कि ऊपर उल्लिखित अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के बयान ने गंभीर संदेह पैदा किया है और सन्देह हो रहा है। इसलिए, इसे दूसरे याचिकाकर्ता तक बढ़ाया जाना चाहिए।

23. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही कहा है। पीडब्लू-7 की गवाही पर निर्भरता, जिनके अनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों, गुरदीप सिंह, हरनेक सिंह और सह-अभियुक्त सनी लाल पासवान ने खुलासा किया। 12.06.2000 पर उन्हें पूरी घटना का वर्णन करते हुए बयान जिसने न तो कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति दर्ज की है न ही उचित समय के भीतर उक्त बयान का खुलासा किया, बल्कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का खुलासा करने के लिए 16 दिन का समय दिया। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा क्षेत्राधिकार पुलिस को सूचित करना। अतिरिक्त न्यायिक व्यवस्था के बारे में पुलिस को सूचित करने में देरी अभियुक्त के बारे में पीडब्लू-7 द्वारा और कारण नहीं बताया गया है। उसी का खुलासा न करने के लिए उसके द्वारा देने की मांग की गई। पुलिस को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं है और संतोषजनक भी नहीं। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी ने इस संबंध में द्वारकादास गेहनमल के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर उचित रूप से भरोसा किया है - उक्त मामले में गवाह का आचरण जो असंगत है। एक साधारण मनुष्य के आचरण के साथ। उपरोक्त मामले में सभी चार तथ्यों के साथ की गई टिप्पणियां हाथ में मामले की स्थितियों पर लागू होती हैं, कि यदि अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त न्यायिक इकबालिया बयान दिया गया था जैसा कि कहा गया है। उसके द्वारा निचली अदालत के समक्ष अपने बयान

में सच होना था, यह उसका कर्तव्य था कि वह तुरंत पुलिस या मृतक के रिश्तेदारों को इसका खुलासा करे। यह उनके द्वारा नहीं किया गया है और इसलिए उनके साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं।

24. अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर रूप है। अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों पर अधिरोपित किया जाए। समर्थन मेंइस प्रस्ताव के, पंचो के मामले के प्रासंगिक पैराग्राफ इन्हें नीचे निकाला गया हैः

> "16. ए-1, प्रथम द्वारा की गई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति का उपयोग इसके निर्माता के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन सावधानी के मामले में, अदालतें पुष्टि की तलाश करती हैं। अभिलेख पर अन्य साक्ष्य से भी ऐसा ही है। गोपाल साह बनाम बिहार राज्य इस न्यायालय ने एक अतिरिक्त न्यायिक मामले पर विचार करते हुए
>
> स्वीकारोक्ति ने माना कि एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति इसके सामने है, एक कमजोर सबूत और अदालतें ठोस परिस्थितियों की एक श्रृंखला के अभाव में, भरोसा करने के लिए अनिच्छुक हैं। उस पर दोषसिद्धि दर्ज करने के उद्देश्य से। इसलिए, हमें पहले यह पता लगाना चाहिए कि क्या

अतिरिक्त-न्यायिक ए-1, प्रथम की स्वीकारोक्ति आत्मविश्वास को प्रेरित करती है और फिर यह पता लगाती है कि क्या अन्य ठोस परिस्थितियाँ हैं इसका समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड करें"।

25. इस न्यायालय ने आगे कहा किः (कश्मीरा सिंह मामला, एआईआर पी. 160, पैरा 10)

"10.....ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां न्यायाधीश नहीं है। अन्य साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करने के लिए तैयार स्वयं विश्वास करते हुए कि सहायता के बिना क्या स्वीकारोक्ति, वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा।"

27. हरिचरण मामले में इस अदालत ने आगे कहा कि धारा 30 अदालत को केवल स्वीकारोक्ति लेने में सक्षम बनाती है। हिसाब में। यह अदालत पर लेने के लिए अनिवार्य नहीं है स्वीकारोक्ति को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है सह-अभियुक्त के विरुद्ध। जहाँ अभियोजन पक्ष निर्भर करता है एक अभियुक्त का दूसरे के विरुद्ध स्वीकारोक्ति, उचित दृष्टिकोण इस तरह के खिलाफ अन्य सबूत पर विचार करना है एक अभियुक्त और यदि उक्त साक्ष्य प्रतीत होता है संतोषजनक और न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए इच्छुक है कि उक्त साक्ष्य उक्त व्यक्ति के खिलाफ बनाए गए आरोप को कायम रख सकता है। अभियुक्त, अदालत

स्वीकारोक्ति की ओर मुड़ती है स्वयं को आश्वस्त करते हुए कि वह निष्कर्ष जिसके लिए वह इच्छुक है अन्य साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालना सही है।"

इसके अलावा, सहदेवन के मामले के प्रासंगिक पैराग्राफ हैं - इसके तहत कार्य किया गयाः

"14. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति एक सबूत कमजोर टुकड़ा है। जहाँ कहीं भी न्यायालय, देय होने पर अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य की सराहना, एक अतिरिक्त न्यायिक आधार पर दोषसिद्धि स्वीकारोक्ति का इरादा रखती है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वही प्रेरित करता है। विश्वास और अन्य द्वारा पुष्टि की जाती है। अभियोजन साक्ष्य। यदि, तथापि, अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति भौतिक विसंगतियों से ग्रस्त है या अंतर्निहित असंभवताएँ और अभियोजन संस्करण के अनुसार ठोस प्रतीत नहीं होती हैं, यह हो सकता है। अदालत के लिए इस तरह के कबूलनामे पर दोषसिद्धि को आधार बनाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत इस तरह के साक्ष्य पर विचार करें। फैसला देने में पूरी तरह से उचित होगी -

16. उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्णयों के उचित विश्लेषण पर इस न्यायालय के सिद्धांतों को बताना उचित होगा। जो एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति बना देगा। आधार बनाने में सक्षम साक्ष्य का स्वीकार्य टुकड़ा एक अभियुक्त को दोषी ठहराना। ये उपदेश मार्गदर्शन करेंगे। मामलों की

सच्चाई से निपटने के दौरान न्यायिक दिमाग जहाँ अभियोजन पक्ष बहुत अधिक न्यायेतर पर निर्भर करता है। अभियुक्त द्वारा की गई कथित स्वीकारोक्तिः

(i) अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अपने आप में कमजोर सबूत है। अदालत द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। अधिक सावधानी और सावधानी बरतें।

(ii) यह स्वेच्छा से किया जाना चाहिए और सत्यवादी होना चाहिए।

(iii) इससे आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए।

(iv) अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अधिक हो जाती है। विश्वसनीयता और साक्ष्य मूल्य यदि यह ठोस परिस्थितियों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित है और आगे है। अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्टि की गई।

(v) अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को आधार बनाना। दृढ़ विश्वास के कारण, यह किसी भी सामग्री से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। विसंगतियाँ और अंतर्निहित असंभवताएँ।

(vi) इस तरह के कथन को अनिवार्य रूप से इस तरह साबित करना होगा कोई अन्य तथ्य और कानून के अनुसार।''

25. रिलायंस ने इस न्यायालय के फैसलों पर रखा सहदेवन के मामले (ऊपर) के मामले का समर्थन करता है। अपीलार्थी इसलिए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा पीडब्लू-7 के साक्ष्य पर निर्भरता अदालत अपीलार्थी को दोषी ठहराएगी और उसे अपराध के लिए सजा सुनाएगी आई.पी.सी. की धारा 201 के तहत कानून में गलत है क्योंकि उन्होंने पी. डब्ल्यू.-7 की गवाही की सराहना नहीं की है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में अतिरिक्त न्यायिक 824 के प्रश्न पर उपरोक्त संदर्भित मामले कहा जाता है कि कुछ अभियुक्तों ने उसे कबूलनामा दिया था। उसी दिन या उचित समय के भीतर पुलिस या परिवार को इसका खुलासा न करना। मृतक के सदस्य आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखने के लिए गवाही के रूप में स्वीकार किया गया। 16 दिनों के बाद उसने अधिकार क्षेत्र की पुलिस को इसका खुलासा किया था। जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उक्त का आचरण गवाह अप्राकृतिक है और उस पर विश्वास करना असंभव है और उसका आचरण एक आम इंसान का नहीं है।

26. अतः उस पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश अपीलार्थी ने 2008 सी.आर.एल.ए संख्या 1279 पर निर्भरता रखते हुए पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 की गवाही के साथ पीडब्लू-7 की गवाही में बड़ी विसंगति है और इसलिए इसमें अपील की गई है। जहाँ तक तेजिंदर सिंह की बात है, उन्हें सफल होना चाहिए।

27. जहाँ तक संबंधित अपीलों में अन्य अपीलार्थियों का संबंध है। संबंधित हैं, सत्र न्यायालय ने पीडब्लू-7, पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 के साक्ष्य पर भरोसा करने के बाद उनके खिलाफ आरोपों पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं, जो कानून में पूरी तरह से असमर्थनीय है। न तो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने उनकी गवाही की फिर से सराहना करके ठीक से जांच की है। आरोपों पर निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए भी ऐसा ही है। कथावाचक। उन्हें दोषी ठहराना और सजा देना अविश्वसनीय है। निचली अदालतें अभिलेख पर साक्ष्य की उचित रूप से सराहना करनी चाहिए थी और उन्हें पीडब्लू 8 के साक्ष्य के बयान पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। इस कारण से कि न तो उन्होंने कथित का खुलासा किया है। अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध और अन्य अभियुक्त ने न तो निचली अदालत के समक्ष या गाँव के किसी भी व्यक्ति के सामने गवाही दी। उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कथित अपराधों का खुलासा न करने के लिए कहा गया है। अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों द्वारा किया गया कि उन्हें

डर के कारण पकड़ लिया गया था और इसलिए, उन्होंने ग्रामीणों में से किसी को भी घटना का खुलासा नहीं किया, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह है अप्राकृतिक। इसलिए, पीडब्लू-8 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 की गवाही स्पष्ट रूप से होगी। यह दिखाने के लिए जाएँ कि कथन के संबंध में विसंगति है। अभियुक्त द्वारा किए गए अपराधों में से। इसलिए, निचली अदालतों को पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 के साक्ष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और यह निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए था कि अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए। दोनों अदालतों ने गंभीर गलती की है। पीडब्लू-8 की अविश्वसनीय गवाही पर भरोसा रखना और पीडब्लू-9 और दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित करना उनके खिलाफ।

28. इसके अलावा, दूसरे गवाह, पीडब्लू-10 का साक्ष्य, जिसने बताया कि 24.5.2000 को लगभग 8.00 बजे, वह निम्मो के साथ खेतों से चारा लाने गई थी। लगभग 9.00 बजे. सुबह जब वे वापस आ रहे थे तो देखा कि सन्नी लाल खेत में पानी लगा रहा था। इसी बीच उसने देखा कि मृतक सीसो भी हाथ में जूट का कपड़ा लेकर खेत में घुसी है. और कुछ देर बाद उसने दूसरे आरोपी बिंदर और काका को ट्यूबवेल की तरफ जाते हुए देखा. इस प्रकार, उक्त अभियुक्त द्वारा किया गया कथित अपराध भी हमारे

द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा नीचे की अदालतों द्वारा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पीडब्लू-7 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के बारे में कहा गया है कि सुप्रा में संदर्भित कुछ आरोपियों द्वारा उससे की गई थी, जिसे अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। नीचे की अदालतें. इस संबंध में, हमने 2008 सीआरएल्.ए. संख्या 1279 में अपीलकर्ता तेजिंदर सिंह के मामले पर विचार करते समय इस न्यायालय के केस कानून के संदर्भ में अपने कारणों और निष्कर्षों को पहले ही दर्ज कर लिया है। इस निर्णय के पहले भाग में की। यही कारण इन अपीलकर्ताओं के मामले में भी लागू होते हैं। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में पीडब्लू-7 के असंभव और अप्राकृतिक साक्ष्य को विश्वसनीयता देने में गंभीर त्रुटि की है क्योंकि उसने पुलिस को सूचित करने में 16 दिन का समय लिया था। उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कथित अपराध के लिए अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों की दोषसिद्धि न केवल कानून की दृष्टि से गलत है, बल्कि कानून की दृष्टि से भी त्रुटिपूर्ण है और इसलिए, वह उत्तरदायी है।

29. इसके अलावा, डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा की गई पोस्टमार्टम जांच में सीसो के मृत शरीर पर निम्नलिखित चोटें देखी गईं जो मामले के लिए प्रासंगिक हैं:

"(ए) चेहरे और गर्दन के बाईं ओर 14x3 सेमीx5 सेमी गहरा कटा हुआ घाव, चेहरे और गर्दन के पार्श्व भाग पर क्षैतिज रूप से रखा हुआ, पूर्वकाल में और चेहरे की मध्य रेखा से 8 सेमी और नीचे 7 सेमी था। बाईं आंख की भौंह, घाव के आसपास थक्के मौजूद थे। आंतरिक जुगलर नस और बाहरी कैरोटिड धमनी कट गई थी। घाव के किनारों का पीछे हटना देखा गया था।

(एच) चोट का कोई बाहरी निशान नहीं था, लेबिया, मेजा और माइनर स्वस्थ थे। कोई रक्त या स्राव नहीं, इंटोरिटिस से स्लाइड 1 और 3 तैयार की गईं। स्वैब 5 एवं 7 तैयार किये गये। प्रति स्पेकुलम जांच में योनि पर चोट का कोई निशान नहीं दिखा, गर्भाशय ग्रीवा सामान्य थी और वीर्य विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षक, पटियाला के पास भेजा गया था।"

डॉक्टरों की राय के अनुसार मृत्यु का कारण चोट संख्या (ए) के कारण सदमा और रक्तस्राव था, जो चेहरे और गर्दन पर था और प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था।

30. हमारे सुविचारित विचार में, ट्रायल कोर्ट के मूल रिकॉर्ड से अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान को देखने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि

अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन का मामला अनुपस्थिति में संदेह और संदेह पैदा करता है। रिकॉर्ड पर कानूनी सबूत हैं और इसलिए उन्हें बरी किए जाने के लिए आरोपियों के लाभ के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

31. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, इसके माध्यम से जाने के बाद अभियोजन पक्ष के गवाहों का मूल अभिलेख से बयान निचली अदालत में, हम संतुष्ट हैं कि अभियोगों पर अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला कानूनी साक्ष्य के अभाव में संदेह और संदेह पैदा करता है। अभिलेख पर और इसलिए उन्हें अभियुक्तों को बरी करने के लिए उनके लाभ के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निचली अदालतों ने उसको दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है। उनके खिलाफ बनाए गए आरोपों पर अपीलकर्ता परिस्थितिजन्य साक्ष्य, भले ही घटनाओं की श्रृंखला अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थियों/अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दोषी ठहराने के लिए साबित नहीं की जाती है। आरोपों पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष इस संबंध में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ है।

32. हमने इनके संबंध में पूरे मामले की जांच की है। अपीलार्थी और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कोई नहीं है। दोषी ठहराने और सजा देने के लिए अभिलेख पर सामग्री साक्ष्य याचिकाकर्ता। पूर्वगामी कारणों से, हम

इस मामले को स्वीकार करते हैं। संबंधित अपीलों में अपीलार्थी तदनुसार, उनके अपील की भी अनुमति दी जाती है और दोषसिद्धि और सजा निर्धारित की जाती है और यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

33. अन्य अभियुक्त, अर्थात्। गुरदीप सिंह जिनके पास नहीं है अभियुक्त को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। निर्णय और जिसे भी दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, उनके अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करते हुए संविधान, उसे भी वही लाभ देता है और उसे तुरंत रिहा करने का भी निर्देश दिया जाता है यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है।

34. पूर्वगामी कारणों से, सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है। 35. अपीलार्थी के जमानत बांड-तेजिंदर सिंह, जो है जमानत पर, इसके द्वारा रिहा कर दिए जाते हैं।

आर. पी.

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कविता मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।